

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति



असल बदलाव संख्या में नहीं, बल्कि इस बात में है कि अब लेन-देन कौन कर रहा है। ऑटो-रिक्शा चालक अब क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। गांवों की मंडियों में लेन-देन तुरंत निपटाए जा रहे हैं। सड़क किनारे विक्रेताओं को अब छुट्टे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक घरेलू कामगार भी एक साधारण स्मार्टफोन की मदद से कुछ ही सेकंड में राज्यों के बीच पैसे भेज सकता है। इस प्रणाली में शहरी और ग्रामीण, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की खाई धीरे-धीरे खत्म हो रही है, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है।

कुछ समय पहले तक, एक साधारण वित्तीय लेन-देन के लिए समय, मेहनत और धैर्य जरूरी होता था। बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। पैसे भेजने के लिए बैंक जाना, फॉर्म भरना और पुष्टि के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। भारत में उन लाखों लोगों के लिए जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं थी, इसका मतलब था वित्तीय प्रणाली से बाहर रहना। हालांकि, ऐसा भारत अब अतीत बन चुका है। भारत की वित्तीय यात्रा सदियों में विकसित हुई है-वस्तु विनिमय प्रणाली और कौड़ी सीप से लेकर सिक्कों, कागजी मुद्रा और चेक तक। अपने आधुनिक इतिहास के अधिकांश समय, लेन-देन का प्रमुख माध्यम नकदी बना रहा। हालांकि चेक और डिमांड ड्राफ्ट ने भुगतान को औपचारिक रूप दिया, लेकिन वे धीमे थे और केवल सीमित वर्ग तक ही सुलभ थे। बैंकिंग ढांचा मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, जिससे ग्रामीण और दूरदराज की आबादी वंचित रह गई।

2000 के शुरुआती दशक ने भुगतान प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2004 में रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और 2010 में इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) जैसी प्रणालियां शुरू कीं, जिससे तेज़ और 24 घंटे धन का हस्तांतरण संभव हुआ। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, लेकिन इनकी पहुंच मुख्यतः उन्हीं लोगों तक सीमित रही जो पहले से ही बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा थे। भारत की एक बड़ी आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रही, उनकी ऋण, बीमा या सुरक्षित बचत जैसी सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी। एक स्केलेबल, समावेशी और रियल-टाइम डिजिटल ढांचे की कमी का मतलब था कि आर्थिक विकास के लाभ सभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे थे। एक परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता स्पष्ट थी, और इसी आवश्यकता ने भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की नींव रखी।

जेएएम ट्रिनिटी: डिजिटल बैंकिंग में एक बुनियादी परिवर्तन

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति एक मज़बूत आधारभूत संरचना पर टिकी है, जिसमें तीन प्रमुख स्तंभ शामिल हैं - प्रधानमंत्री जन-धन योजना (जन धन), आधार, और मोबाइल कनेक्टिविटी। इन्हें सामूहिक रूप से जेएएम ट्रिनिटी कहा जाता है। प्रत्येक स्तंभ का अपना अलग उद्देश्य है, लेकिन साथ मिलकर इन्होंने लीकेज को कम करके, औपचारिक बैंकिंग में भरोसा बढ़ाकर, और नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जुड़ने के लिए तैयार करके वित्तीय इकोसिस्टम को मज़बूत किया है।

UPI भारत का
सुपरफास्ट पेमेंट सिस्टम!
694 बैंक एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े

जनवरी 2026 में
21.70
बिलियन+
ट्रांज़ैक्शन



₹28.33
लाख करोड़+
का लेन-देन

UPI इन देशों में भी उपलब्ध

UAE | सिंगापुर | भूटान | नेपाल | श्रीलंका | फ्रांस | मॉरीशस | कतर



पारस्परिकता ही यूपीआई के तेज़ विस्तार का मुख्य कारण रही है।

2021 में 216 बैंकों से बढ़कर जनवरी 2026 तक 691 बैंकों तक पहुंचते हुए, यह एक एकीकृत भुगतान संरचना बन गई है, जहां उपयोगकर्ता अपने किसी भी बैंक या प्लेटफॉर्म से आसानी से लेन-देन कर सकते हैं। इसके साथ ही, इसकी कम लागत वाली संरचना ने व्यक्तियों और व्यापारियों दोनों के लिए

बाधाओं को कम किया है और बैंकों तथा फिनटेक कंपनियों के बीच नवाचार को बढ़ावा दिया है।

जैसे-जैसे यूपीआई का विस्तार हुआ, इसका प्रभाव केवल भुगतान की सुविधा तक सीमित नहीं रहा। इसने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वित्तीय प्रणाली में भागीदारी के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। डिजिटल लेन-देन अधिक सुलभ, विश्वसनीय और विभिन्न क्षेत्रों व आय वर्गों में व्यापक रूप से अपनाए जाने लगे।

सिर्फ सहूलियत नहीं, बल्कि वित्तीय सशक्तीकरण

यूपीआई केवल भुगतान को सरल बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने वित्तीय प्रणाली में भागीदारी के स्वरूप को भी बदल दिया है। त्वरित और कम लागत वाले लेन-देन को सक्षम बनाकर, इसने नकदी पर निर्भरता को कम किया है, दक्षता बढ़ाई है और लाखों लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच खोली है। छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यह बदलाव

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने बड़े पैमाने पर शून्य-बैलेंस खाते खुलवाने के माध्यम से लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जिससे सबसे वंचित वर्ग भी वित्तीय रूप से जुड़ सका है। आधार ने एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रदान करके इस बुनियाद को और मजबूत किया है, जिससे बेरोकटोक सेवाएं प्रदान करने का सटीक लक्ष्य और निर्बाध वितरण संभव हुआ है। इन दोनों के पूरक के रूप में, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट पहुंच के तेजी से विस्तार ने नागरिकों को संचार, प्रमाणीकरण और लेन-देन के लिए एक सुविधाजनक और रियल-टाइम माध्यम प्रदान किया है। इस एकीकृत ढांचे को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से पूर्ण रूप मिला, जिसने सरकारी लाभों को सीधे बैंक खातों में पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। बिचौलियों को कम करके और पारदर्शिता बढ़ाकर, डीबीटी ने दक्षता में सुधार किया है और साथ ही डिजिटल प्रणालियों में विश्वास भी मजबूत किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिवर्तन केवल पहुंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सहभागिता को भी सक्षम बनाया है। जैसे-जैसे नागरिक डीबीटी से जुड़े, वे डिजिटल वित्तीय लेन-देन के प्रति अधिक परिचित होते गए, जिससे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यूपीआई: भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव

2016 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की, एक ऐसी प्रणाली जिसने भारत में पैसे के लेन-देन के तरीके को मूल रूप से सरल बना दिया। अपने मूल में, यूपीआई किसी भी बैंक खाते को एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से दूसरे खाते से जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे विस्तृत बैंकिंग जानकारी साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यूपीआई का विचार अपने आप में विलक्षण था। अब न तो खाता नंबर याद रखने की ज़रूरत है और न ही जटिल विवरण भरने की। यह प्रणाली खाता संख्या और आईएफएससी कोड जैसे जटिल इनपुट को एक आसान इंटरफेस से बदल देती है। उपयोगकर्ताओं को केवल एक मोबाइल नंबर, एक यूपीआई आईडी और सुरक्षित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे वे तुरंत धन हस्तांतरण कर सकते हैं। लेन-देन रियल-टाइम में होते हैं, 24x7 उपलब्ध रहते हैं, और विभिन्न बैंकों तथा ऐप्स के बीच सहज रूप से काम करते हैं। यह

UPI
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

मेमेट का स्मार्ट और भरोसेमंद तरीका!

64 करोड़+ ट्रांजैक्शन
यूपीआई से हर दिन होते हैं

6.5 करोड़
व्यापारियों को सेवा,
694 बैंक
UPI पर लाइव

भारत में कुल रिटेल पेमेंट ट्रांजैक्शन में **81% से अधिक यूपीआई से** होते हैं

मार्च 2026 में **22.64 बिलियन** ट्रांजैक्शन, **₹29.52 लाख** करोड़ का लेन-देन

विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऋण, बीमा और बचत के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। असल बदलाव संख्या में नहीं, बल्कि इस बात में है कि अब लेन-देन कौन कर रहा है। ऑटो-रिक्शा चालक अब क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। गांवों की मंडियों में लेन-देन तुरंत निपटाए जा रहे हैं। सड़क किनारे विक्रेताओं को अब छुट्टे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक घरेलू कामगार भी एक साधारण स्मार्टफोन की मदद से कुछ ही सेकंड में राज्यों के बीच पैसे भेज सकता है। इस प्रणाली में शहरी और ग्रामीण, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की खाई धीरे-धीरे खत्म हो रही है, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है।

साथ ही यूपीआई अब एक व्यापक वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है। यूपीआई लाइट तेज और छोटे मूल्य के भुगतानों को आसान बनाता है, जबकि यूपीआई ऑटो पे उपयोगिता बिलों और सब्सक्रिप्शन जैसे आवर्ती खर्चों को सरल और स्वचालित करता है। यूपीआई पर क्रेडिट की सुविधा इसके दायरे को और आगे बढ़ाती है, जिससे पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों तक पहुंच संभव होती है। इस मजबूत अवसरचना के आधार पर, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां ऋण प्रदान कर रही हैं, पुनर्भुगतान को सक्षम बना रही हैं और जरूरतों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद पेश कर रही हैं, जिससे पूरे देश में औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है।

डिजिटल भुगतान: पहुंच, दक्षता, सुरक्षा और भरोसा

इस विस्तारित इकोसिस्टम के आधार पर, यूपीआई अब देश की रोजमर्रा की आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जो शुरुआत में केवल सहूलियत का साधन था, वह अब एक विश्वसनीय प्रणाली बन गया है, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों, सभी की मदद करता है। उपयोगकर्ताओं के लिए, इसका अनुभव सरलता और विश्वास से परिभाषित होता है। लेन-देन कभी भी, कहीं से भी, एक ही एप्लिकेशन के माध्यम से किए जा सकते हैं, जो कई बैंक खातों से जुड़ा होता है। संवेदनशील बैंकिंग जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती, और अंतर्निहित सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि भुगतान सुरक्षित रहें। ऐप्स के भीतर उपलब्ध सहायता सुविधाएं शिकायत निवारण को भी आसान बनाती हैं, जिससे यह प्रणाली पहली बार उपयोग करने वालों के लिए भी सुलभ हो जाती है।

डिजिटल भुगतान में विश्वास को और मजबूत करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 1 अप्रैल, 2026 से डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए उन्नत प्रमाणीकरण तंत्र लागू किए हैं। दो-स्तरीय प्रमाणीकरण का यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि हर लेन-देन कई स्तरों पर सत्यापित हो-जैसे पिन, बायोमेट्रिक्स या सुरक्षित टोकन के साथ ओटीपी। इससे धोखाधड़ी के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

व्यापारियों के लिए, यह नकदी संभालने की आवश्यकता के बिना तेज और कुशल तरीके से भुगतान प्राप्त करने का माध्यम प्रदान

करता है। इससे व्यवसायों को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने में मदद मिलती है, खासकर उन ग्राहकों तक जो कार्ड या नकद के बजाय मोबाइल-आधारित भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। चाहे छोटे दुकानों में हो, सड़क बाजारों में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेन-देन तुरंत पूरे होते हैं, जिससे देरी और नकदी प्रबंधन या रिटर्न जैसी परिचालन चुनौतियां कम होती हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, यह मौजूदा प्रणालियों का उपयोग करते हुए सुरक्षित और रियल-टाइम लेन-देन को सक्षम बनाकर सेवा वितरण को बेहतर बनाता है। यह बड़े पैमाने पर व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यापारी भुगतानों का समर्थन करता है, साथ ही मजबूत सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए दक्षता में सुधार करता है और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है।

भारत का नवाचार: वैश्विक प्रभाव

भारत का डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में भी उभरा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने इसकी व्यापकता, दक्षता और समावेशिता को सराहा है। वैश्विक नेताओं, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत की इस उपलब्धि पर गौर किया है कि यूपीआई के माध्यम से हर महीने 20 अरब से अधिक लेन-देन किए जाते हैं, जो किसी भी अन्य रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के मुकाबले बेजोड़ है।

डिजिटल पेमेंट्स में भारत बना ग्लोबल ट्रेंडसेटर!

IMF के अनुसार,

UPI को दुनिया का सबसे बड़ा Fast Payment System

वैश्विक रियल-टाइम पेमेंट्स में
लगभग 49% हिस्सेदारी



UPI इन देशों में भी उपलब्ध

UAE | सिंगापुर | भूटान | नेपाल | श्रीलंका | फ्रांस | मॉरीशस | कतर

यूपीआई अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ चुका है और संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस

और कतर सहित कई देशों में चल रहा है या उनकी भुगतान प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। यह बढ़ता हुआ अंतरराष्ट्रीय विस्तार सीमा-पार लेन-देन को आसान बना रहा है, रकम भेजने में मदद कर रहा है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की भूमिका को और मज़बूत कर रहा है।

यूपीआई: भारत की वित्तीय क्रांति का आधार

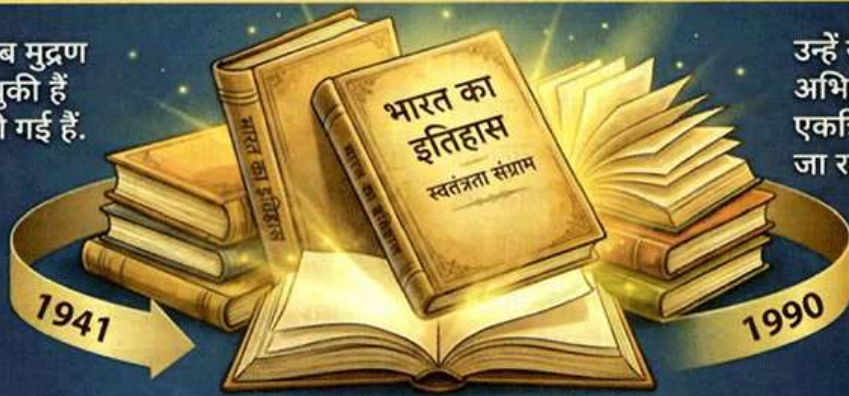
यूपीआई ने वित्तीय रूप से जुड़े और वंचित वर्गों के बीच की खाई को समाप्त कर दिया है। आज ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भारत भी महानगरों की तरह ही तेज़ी और सहजता से लेन-देन कर रहा है। एक स्वदेशी प्रणाली, जिसे एक दशक से भी कम समय में विकसित किया गया, आज विश्व में अग्रणी बन चुकी है। जो पहल कभी बैंकिंग से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए शुरू हुई थी, वह अब रियल-टाइम भुगतान के लिए वैश्विक मानक बन गई है। कतारों से क्यूआर कोड तक की यह यात्रा समावेशी नवाचार की शक्ति को दर्शाती है। यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है; यह लोगों का मंच है। इसने वित्तीय लेन-देन को तेज़, सरल, पारदर्शी और वास्तव में समावेशी बना दिया है। ऐसा करते हुए, इसने न केवल यह बदला है कि भारत कैसे भुगतान कर रहा है, बल्कि यह भी कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। □

(पसूका से साभार)

अपील

प्रकाशन विभाग देशभर में एक राष्ट्रीय अभिलेखन एवं डिजिटलीकरण पहल के अंतर्गत वर्ष 1941 से 1990 के बीच डीपीडी द्वारा प्रकाशित दुर्लभ एवं ऐतिहासिक महत्व की पुस्तकों को संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। यदि आपके पास 1990 से पूर्व प्रकाशित प्रकाशन विभाग की कोई भी पुस्तक उपलब्ध हो, तो कृपया उस पुस्तक की फोटो एवं विवरण (प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, विषय-वस्तु आदि) ई-मेल के माध्यम से bm-dpd@gov.in पर साझा करने का कष्ट करें।

कई पुस्तकें अब मुद्रण से बाहर हो चुकी हैं या दुर्लभ हो गई हैं।



उन्हें खोजकर अभिलेखागार में एकत्रित किया जा रहा है।

📷 पुस्तक की फोटो | 📖 प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या | 🔍 विषय-वस्तु आदि

ई-मेल करें (Email):
bm-dpd@gov.in

(आपके सहयोग से हमारा गौरवमय इतिहास सुरक्षित होगा)



सूचना एवं
प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF
INFORMATION AND
BROADCASTING



Publications Division
प्रकाशन विभाग